



Neutral Citation No- 2026: AHC:174056

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 8848/2026

आशीष मिश्रा

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के लिए अधिवक्ता : गिरजा शंकर मिश्रा, मोहम्मद गौस अली, सोम्या द्वादश श्रेणी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : सौम्या द्वादश श्रेणी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
- वर्तमान 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदन, दिनांक 11.11.2025 के संज्ञान/समन आदेश तथा वाद संख्या 291/2025 (राज्य बनाम सतीश कुमार मिश्रा एवं अन्य) की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या 0443/2025, धारा 223, 244, भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना-हंडिया, कमिश्नरेट प्रयागराज से उद्भूत है तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 08 के न्यायालय में लंबित है।
- सूचनाकर्ता, जो लेखपाल के पद पर तैनात है, ने आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए यह आरोप लगाया कि ग्राम सराय सिविल उर्फ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



खण्डिहा में जिलाधिकारी हंडिया के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर/पूर्व विधायक विजय कुमार मिश्रा, पुत्र रामदेव मिश्रा की सम्पत्ति की जाँच की गई, जो गैंगस्टर अधिनियम के मुकदमा अपराध संख्या 89/2003, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा सीएलए अधिनियम एवं धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के प्रकरण में, दिनांक 24.10.2009 के आदेश के माध्यम से गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन तत्कालीन जिलाधिकारी, इलाहाबाद (प्रयागराज) द्वारा कुर्क की गई थी तथा उक्त सम्पत्ति के प्रशासक उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी थे। अतः सूचनाकर्ता ने जाँच की और पाया कि आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों ने आराजी संख्या 578मि./0.2970 हेक्टेयर भूमि पर दो कमरों एवं टीन शेड का निर्माण कर रखा है तथा उस पर खेती कर रहे हैं।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है और आवेदक के चाचा के साथ प्रतिद्वंद्विता के कारण इस प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक विजय कुमार मिश्रा का भतीजा है और उसे सह-आरोपी से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता है और अलग रह रहा है। आवेदक के खिलाफ आरोप झूठा, निराधार है और किसी भी सबूत द्वारा समर्थित नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन न्यायिक दिमाग के आवेदन के बिना है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया है और सरसरी तौर पर आवेदक के खिलाफ समन जारी किया है। आवेदक के अधिवक्ता ने **जेएम लेबोरेटरीज और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2025 (2) एएलडी (सीआरएल) 265 (एससी)** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह ने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान के अवलोकन पर, प्रथम दृष्टया आवेदक और आवेदक के खिलाफ अपराध का खुलासा करता है और जबरन और जानबूझकर सील तोड़ी और दो कमरों का निर्माण किया। इसके बाद यह कहा जाता है कि आक्षेपित समन आदेश न्यायसंगत और उचित है और विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध साक्ष्यों को देखने के बाद, विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक को तलब किया है।

6. विद्वान मजिस्ट्रेट ने 11.11.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" मु0अ0सं0 443/25 में प्रकरण में विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।



समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया अभियुक्तगण सतीश मिश्रा, आशीष मिश्रा, प्रेमशंकर मिश्रा उर्फ बब्बू, बिन्दू देवी, के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया जाता है। अभियुक्तगण सतीश मिश्रा, आशीष मिश्रा, प्रेमशंकर मिश्रा उर्फ बब्बू, बिन्दू देवी उपरोक्त के विरुद्ध धारा 223, 244 बीएनएस के अपराध के विचारण हेतु सम्मन जारी हो। दर्ज रजिस्टर हो। वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण सतीश मिश्रा, आशीष मिश्रा, प्रेमशंकर मिश्रा उर्फ बब्बू, बिन्दू देवी दिनांक 01.12.2025 को पेश हो।"

7. विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है और उपलब्ध केस डायरी और अभिलेख को देखने के बाद प्रक्रिया जारी की है। विवेचना अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के अवलोकन पर, प्रथम दृष्टया अपराध, आवेदक के खिलाफ खुलासा करता है।

8. प्रमिला देवी और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 886 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार माना है:

"14. सबसे पहले, क्या अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त को संज्ञान लेते समय संज्ञान लेने के लिए विस्तृत कारण दर्ज करने होंगे? दूसरे, क्या एफआईआर स्वयं दुर्भावनापूर्ण इरादे से स्थापित की गई थी और इसे रद्द किया जाना था?

15. पहले मुद्दे पर आते हुए, हमें यह दर्ज करने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत था। दिनांक 13.06.2019 के आदेश का अवलोकन करने से पता चलता है कि अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त ने कहा है कि केस डायरी और केस अभिलेख ? का अवलोकन किया गया है, जिसने अपीलकर्ताओं सहित अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए), 406 और 420 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (जी) के तहत बनाए गए प्रथम दृष्टया प्रकरण का खुलासा किया है। इसके अलावा, हम अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त के दृष्टिकोण को सही पाते हैं क्योंकि संज्ञान लेते समय, उसने सबसे पहले अपने सामने की सामग्रियों पर अपना दिमाग लगाया ताकि यह राय बनाई जा सके कि क्या कोई अपराध किया गया है और उसके बाद उन व्यक्तियों की पहचान करने के पहलू पर चला गया जिन्होंने अपराध किया है। तदनुसार, प्रक्रिया अगले चरण में जाती है; ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ समन या वारंट जारी करना, जैसा भी वाद हो।



16. इस वाद में, हम पाते हैं कि अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त ने एक निष्कर्ष दर्ज करते समय संज्ञान लिया है कि - केस डायरी और केस अभिलेख के अवलोकन से, अपीलकर्ताओं सहित अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम दृष्टया वाद बनाया गया था। भूषण कुमार बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2012) 5 एससीसी 424 में, इस न्यायालय ने माना कि संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि यह एक तर्कसंगत आदेश नहीं था; प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:

'14. इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह कहा गया है कि संहिता की धारा 204 के तहत समन आदेश में स्पष्ट कारणों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह जरूरी है कि मजिस्ट्रेट ने आरोपों पर ध्यान दिया हो और पुलिस रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और उसके साथ दायर सामग्री पर अपना दिमाग लगाया हो।

15. कांति भद्र शाह बनाम पश्चिम बंगाल की स्थिति [(2000) 1 एससीसी 722: 2000 एससीसी (आपराधिक) 303] निम्नलिखित मार्ग इस संदर्भ में उपयुक्त होगा: (एससीसी पी. 726, पैरा 12)

12. यदि कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करने के कारणों को दिखाते हुए एक आदेश लिखना चाहिए, तो पहले से ही बोझ से दबे ट्रायल कोर्ट पर इस तरह के अतिरिक्त काम का बोझ क्यों डाला जाना चाहिए। अदालत की प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए सभी संभावित उपायों को अपनाने और टालने योग्य देरी के कारण आने वाली सभी बाधाओं को रोकने के उपायों को तैयार करने का समय आ गया है। यदि एक मजिस्ट्रेट को विभिन्न चरणों में विस्तृत आदेश लिखना है, केवल इसलिए कि अधिवक्ता सभी चरणों में तर्कों को संबोधित करेगा, तो ट्रायल अदालतों में कार्यवाही की धीमी गति से प्रगति को और धीमा कर दिया जाएगा। हमें मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों के कई पृष्ठों के अंतरिम आदेश मिल रहे हैं। हम इस बात की सराहना कर सकते हैं कि यदि उनके समक्ष कार्यवाही को समाप्त करने के लिए ऐसा विस्तृत आदेश पारित किया गया है। लेकिन अन्य चरणों में विस्तृत आदेश लिखना काफी अनावश्यक है, जैसे कि प्रक्रिया जारी करना, अभियुक्त को हिरासत में भेजना, आरोप तय करना, मुकदमे में अगले चरणों में ले जाना।

(महत्व प्रदत्त)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. नगाववा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजालगी [(1976) 3 एससीसी 736: 1976 एससीसी (आपराधिक) 507] में इस न्यायालय ने माना कि यह मजिस्ट्रेट का प्रांत नहीं है कि वह मामले के गुण-दोष पर विस्तृत चर्चा करे। आगे यह माना गया कि यह तय करने में कि क्या एक प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए, मजिस्ट्रेट शिकायत के चेहरे पर या आरोपों के समर्थन में शिकायतकर्ता के नेतृत्व में साक्ष्य में दिखाई देने वाली असंभवताओं को ध्यान में रख सकता है। मजिस्ट्रेट को इस मामले में एक निस्संदेह विवेक दिया गया है और विवेक का प्रयोग उसके द्वारा न्यायिक रूप से किया जाना है। आगे यह माना गया था कि: (एससीसी पी. 741, पैरा 5)

“5. एक बार जब मजिस्ट्रेट ने अपने विवेक का प्रयोग कर लिया है, तो यह उच्च न्यायालय या यहां तक कि इस न्यायालय के लिए नहीं है, कि वह मजिस्ट्रेट के लिए अपने विवेक को प्रतिस्थापित करे या यह पता लगाने के लिए कि शिकायत में लगाए गए आरोप, यदि साबित हो जाते हैं, तो अंततः अभियुक्त की दोषसिद्धि में समाप्त हो जाएंगे या नहीं।”

17. आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक बनाम रोशनलाल अग्रवाल [(2003) 4 एससीसी 139: 2003 एससीसी (आपराधिक) 788] में इस न्यायालय ने पैरा 9 में, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पीपी. 145-46)

9. इस प्रश्न को निर्धारित करने में कि क्या कोई प्रक्रिया जारी की जानी है या नहीं, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना होगा कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है और क्या दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार है। क्या सबूत दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है, यह केवल मुकदमे में निर्धारित किया जा सकता है न कि जांच के चरण में। अभियुक्त को प्रक्रिया जारी करने के चरण में, मजिस्ट्रेट को कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न पर हाल ही में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम मोहन मीकिन्स लिमिटेड [(2000) 3 एससीसी 745] में विचार किया गया था और कांति भद्र शाह बनाम में निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए। पश्चिम बंगाल की स्थिति [(2000) 1 एससीसी 722: 2000 एससीसी (आपराधिक) 303] यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था: (उत्तर प्रदेश प्रदूषण वाद [(2000) 3 एससीसी 745], एससीसी पी. 749, पैरा 6)



“6. विधायिका ने कुछ स्थितियों में कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता पर बल दिया है जैसे कि प्रक्रिया जारी किए बिना शिकायत को खारिज करना। समन जारी करते समय विस्तृत आदेश पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट पर ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। आरोपी को जारी की गई प्रक्रिया को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट ने बोलने का आदेश पारित नहीं किया था।”

18. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम भूपेंद्र कुमार मोदी [(2009) 2 एससीसी 147: (2009) 1 एससीसी (आपराधिक) 679] में इस न्यायालय ने पैरा 23 में, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पृष्ठ 154)

23. यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि जारी करने की प्रक्रिया के चरण में, मजिस्ट्रेट मुख्य रूप से शिकायत में लगाए गए आरोपों या उसके समर्थन में पेश किए गए सबूतों से संबंधित होता है और उसे केवल प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना होता है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

19. यह स्थापित कानूनी स्थिति होने के कारण, मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को केवल इस आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि समन आदेश एक तर्कसंगत आदेश नहीं था। (महत्व प्रदत्त)

17. भूषण कुमार (उपरोक्त) में दृष्टिकोण को महमूद उल रहमान बनाम खजीर मोहम्मद टुंडा, (2015) 12 एससीसी 420 और गुजरात राज्य बनाम अफरोज मोहम्मद हसनफता, (2019) 20 एससीसी 539 में दोहराया गया था। इस न्यायालय ने राखी मिश्रा बनाम बिहार राज्य, (2017) 16 एससीसी 772 ने सोनू गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता, (2015) 3 एससीसी 424 में प्रतिपादित विधि के स्थापित प्रस्ताव को फिर से स्थापित किया, जो निम्नानुसार है:

- a. ‘4. हमने पक्षों की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुना है। हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करने और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में गलती की। एफआईआर के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के खिलाफ क्रूरता का



आरोप लगाया है। सोनू गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता [सोनू गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता, (2015) 3 एससीसी 424: (2015) 2 एससीसी (आपराधिक) 265] में इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया: (एससीसी पी. 429, पैरा 8)

“8.संज्ञान लेने और बुलाने के चरण में मजिस्ट्रेट को केवल अपराध का संज्ञान लेने की दृष्टि से अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता है? यह पता लगाने के लिए कि क्या आरोपी व्यक्तियों को बुलाने के लिए प्रथम दृष्टया वाद बनाया गया है। इस स्तर पर, विद्वान मजिस्ट्रेट को बचाव पक्ष के संस्करण या सामग्री या तर्कों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे शिकायतकर्ता की सामग्री या साक्ष्य के गुणों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट को इस स्तर पर यह पता लगाने के लिए अभ्यास नहीं करना चाहिए कि क्या सामग्री दोषसिद्धि की ओर ले जाएगी या नहीं।

5. आर-2 और आर-4 से आर-9 के खिलाफ संज्ञान लेते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश उपरोक्त निर्णय में निर्धारित विधि के अनुरूप है। यह स्थापित विधि है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है जब अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया वाद नहीं बनता है। अभियोजन के प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप के लिए इस न्यायालय द्वारा लागू परीक्षण यह है कि क्या निर्विवाद आरोप प्रथम दृष्टया एक वाद स्थापित करते हैं।

(महत्व प्रदत्त)“

9. आवेदन में लिए गए आधारों से पता चलता है कि उनमें से कई तथ्य के विवादित प्रश्न से संबंधित हैं। इस न्यायालय का विचार है कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि साक्ष्य की सराहना विचारण न्यायालय का एक कार्य है। यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए इस तरह के अधिकार क्षेत्र को ग्रहण नहीं कर सकता है और विधि के तहत प्रदान की गई मुकदमे की प्रक्रिया को समाप्त नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसलों के श्रृंखला में यह भी तय किया गया है कि आवेदकों के खिलाफ आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इस न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी है। पूर्व-परीक्षण चरण में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का उपयोग



नियमित तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग केवल ऐसे उपयुक्त मामलों में किया जाना चाहिए, जहां यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि संस्था के खिलाफ एक कानूनी रोक है या आपराधिक कार्यवाही जारी है या जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या आरोप-पत्र में लगाए गए आरोप और सामग्री उसी के समर्थन में भरोसा करती है, उनके अंकित मूल्य को लेने और उनकी संपूर्णता को स्वीकार करने पर आरोपी के खिलाफ किसी भी अपराध के कमीशन का खुलासा नहीं करती है। तथ्यों और अभियुक्तों के बचाव के विवादित प्रश्नों को इस पूर्व-परीक्षण चरण में ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

10. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क पर विचार करते हुए और अभिलेख का अवलोकन करते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। सर्वोच्च न्यायालय ने **माणिक बी. बनाम कडपाला श्रीयेस रेड्डी और अन्य, 2023 लाइव लॉ (एससी) 642**, पैरा 6 और 7 के वाद में पारित अपने फैसले में नीचे उद्धृत किया गया है:-

" 6. गवाहों की गवाही भरोसेमंद है या नहीं, इसका पता मुख्य परीक्षा और गवाहों की जिरह से पता लगाया जाना चाहिए जब वे इस तरह के मुकदमे के चरण में बॉक्स में खड़े होते हैं।

7. हमारे विचार में, इस तरह की कवायद सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय अनुमेय नहीं है।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, माणिक बी. बनाम कडपाला श्रीयेस रेड्डी और अन्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 642, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (सीआर) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी.शर्मा, 1992 एससीसी (सीआर) 192 और अंत में झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मो. सरफुल हक और एक अन्य (पैरा-10) 2005 एससीसी (सीआर) 283, उपरोक्त मामले की कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है, जो धारा 528 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की मांग कर सकता है क्योंकि यह किसी भी अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 11.11.2025 का समन आदेश न्यायसंगत और उचित है।



12. धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस आवेदन में गुण-दोष का अभाव है और तदनुसार, निरस्त किया जाता है।

(दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति)

18 अगस्त, 2026

मीनू सिंह